नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुल्लू में हवाई पट्टी के चारों ओर सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास मई, 1995 में 36.89 लाख रुपये की राशि जमा करवाई थी। राज्य सरकार से कार्य शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

Fast Track Power Projects

1456. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the current status of the fast track power projects cleared by Government;

(b) the particulars of Power Projects actually implemented after the annoncement of the new Power Policy in 1991-92; and

(c) the steps being taken to ensure speedier and successful completion of power projects in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) Out of the initial eight fast track private power projects for which Government had agreed to extend counter guarantee, six projects have been cleared by the Central Electricity Authority from techno-economic angle. One of the fast track projects viz. Dabhol Power Project Phase-I (695 MW), has achieved financial closure and construction had been started. However, the construction work on this project has been halted as per the directives of the State Government. Even though financial closure is awaited, construction work has also commenced on two of the other fast track projects viz. Jegurupadu CCGT (216 MW) and Godavari CCGT (208 MW).

(c) Even though the responsibility for ensuring timely completion of the private power projects, including those which are gas based, is that of the concerned State Governments/SEBs, Government of India periodically reviews the progress of all the private power proposals and takes all necessary steps to remove bottlenecks, if any, in the finalisation of the proposals.

वस्त्र निर्यात में कमी

1457. **श्री सोमपाल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1995 में 'इंडियन एक्सप्रेस' में वस्त्र निर्यात में हुई कमी के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मंदी के मुख्य कारण क्या है और क्या सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कोई नई नीति की घोषणा करने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) जी हां। चालू वर्ष के दौरान परिधान निर्यात में वृद्धि की दर में गिरावट आने का मुख्य कारण भारतीय परिधानों के यूरोपीय यूनियन के बाद सबसे बड़े बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका में मांग में गिरावट आना है। आर्थिक मंदी तथा फुटकर खरीद में कमी आने के कारण चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में परिधानों के बाजार में गिरावट आ रही है। सरकार ने 1.1.1996 से 31.12.1998 तक की अवधि के दौरान परिधानों के लिए निर्यात हकदारी नीति को पुन: सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है ताकि उसे सुव्यवस्थित, अधिक प्रभावी तथा स्थाई बनाया जा सके। नई नीति के अनुसार वार्षिक स्तरों का वितरण केवल दो प्रणालियों अर्थात् विगत निर्यात निष्पादन हकदारी प्रणाली तथा पहले आओ पहले पाओ (एफ सी एफ एस) प्रणालियों में 80:20 के अनुपात से किया जाएगा। एफ सी एफ एस प्रणाली में ऐसे निर्यातकों के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ उपलब्ध होगा जो अपने एककों को आधुनिक बनाने के लिए 50 लाख रु॰ से अधिक निवेश करते हैं। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ ऐसे नए निदेशकों को पैर जमाने के लिए प्रोत्साहन देना है।

Unions Functioning in ITDC

1458. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) how many unions are there in ITDC and where each of these unions is presently functioning;

(b) when did the last verification take place and what was the outcome in each case; the details thereof including the strength;